in the various semiarid tropical areas. This constitutes a major segment of the Institute's overall research programme.

बाल भारती, उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, राजेन्द्र नगर, नई दिल्ली के कर्मचारियों को नोटिस

7622. श्री डी० सोहन लाल : क्या शिक्षा समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बाल भारती उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, राजेन्द्र नगर, नई दिल्ली 60 की प्रबन्धक समिति ने विद्यालय के सभी कर्मचारियो को तीन माह का नोटिस दिया है जिसकी अवधि 20 अप्रैल, 1974 को समाप्त हो जाएगी ;

(ख) क्या उक्त नोटिस दिल्ली शिक्षा, अधिनियम, 1973 के उपबन्ध के विरुद्ध है क्योंकि प्रबन्धक समिति ने विद्यालय बन्द करने के सम्बन्ध मे दिल्ली के शिक्षा निदेशक से पूर्व स्वाकृति नही ली थी ;

(ग) यदि हा, तो दिल्ली प्रशासन द्वारा सभी कर्मचारियो को व्यवसायिक सुरक्षा प्रदान करने हेतु क्या कार्यवाही की जा रही है ; और

(घ) क्या दिल्ली प्रशासन सभीकर्मचारियों को एक मई, 1974 से पहले नौकरी दे देगा ताकि उन की सेवाओ मे किसी प्रकार का व्यवधान न आए और उन्हे 30 अप्रैल, 1974 के बाद बेरोजगार न होना पड़े ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उपमंत्री (श्री डी० पी० यादव) : (क) और (ख) . जी, हां।

(ग) दिल्ली प्रशासन ने प्रबन्धको को सूचित किया है कि स्कूल को हाथ में लिए जाने के बारे में प्रबन्धकों को अनुरोध को स्वीकार करना संभव न हो सकेगा क्योंकि उन्होंने इसके लिए विभाग से पूर्वानुमति प्राप्त नहीं की है और इसलिए स्कूल को उन्हें चलाते ही रहना चाहिए।

(घ) प्रश्न नही उठता।

निर्माण आवास को कमी की समस्या

7623. डा० लक्ष्मी नारायण पांडेय : क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या देश मे आवास की कमी की की समस्या गम्भीर रूप धारण करती जा रही है,

(ख) क्या सरकार ने इस सम्बन्ध में कुछ कदम उठाये है ; और यदि हा, तो वे क्या क्या है ;

(ग) क्या आवास सम्बन्धी समस्या हल करने की दिशा मे सहकारी गृह निर्माण समितिया महत्वपूर्ण कार्य कर सकती है; और

(घ) यदि हा, तो सरकार के इस सम्बन्ध मे क्या विचार है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

संसदीय कार्य विभाग तथा निर्माण और आवास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओम मेहता) : (क) देश मे मकानो की काफी अधिक कमी रही है तथा वह अब भी बनी हुई है।

(ख) निम्न तथा मध्यम आय वर्ग के लोगो की आवासीय स्थिति सुधारने की दृष्टि से जिन में औद्योगिक कर्मचारी तथा समुदाय के आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्गों के लोग भी शामिल है, निर्माण और आवास मंत्रालय ने कई सामाजिक आवास योजनायें